BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE, KOLKATA

OA No. 144 of 2024 (EZ)

[Earlier OA No. 655/2024-PB]

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED VAISHAKH MEI HEE SUKH GAI BIHAR KEE 60 NADIYA RET ME HUE TABDIL NADIYAN PAR BHEE HO GAYA ATIKRAMAN APPEARING IN LIVE HINDUSTAN.COM DATED 03.05.2024.

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, RESPONDENT NO. 2

INDEX

S. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No.2 in compliance to the order dated 26.04.2024 of the Hon'ble NGT (EZ).	**1-4**
2.	Copy of the notification S. O. No. 1986 (E) dated 31.07.2014 [**ANNEXURE-R1**].	**5-12**
3.	Copy of the notification S.O. No. 1972(E) dated 14.06.2019 [**ANNEXURE-R2**].	**13-23**

30 JAN 2025

BISHWAMBHAR MAHTO
NOTARY PUBLIC
174/2016-1804J
Ranchi, Jharkhand (India)

ADVOCATES CLERK WELFARE ₹5 पाँच रुपये FIVE
अधिवक्ता कल्याण ₹15 FIFTEEN RUPEES ADVOCATE WELFARE
अधिवक्ता कल्याण FIFTEEN RUPEES ADVOCATE WELFARE
10रु. COURT FEE दस रुपये
Rs.10 COURT FEE INDIA TEN RUPEES

BISHWAMBHAR MAHTO NOTARY PUBLIC Reg. No.-17/2018-1804J Ranchi, Jharkhand (India)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE, KOLKATA

OA No. 144 of 2024 (EZ)

[Earlier OA No. 655/2024-PB]

<u>IN THE MATTER OF:</u>

NEWS ITEM TITLED VAISHAKH MEI HEE SUKH GAI BIHAR KEE 60 NADIYA RET ME HUE TABDIL NADIYAN PAR BHEE HO GAYA ATIKRAMAN APPEARING IN LIVE HINDUSTAN.COM DATED 03.05.2024.

<u>REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, RESPONDENT NO. 2</u>

Authorised under Notaries Act 1952 & Notaries Rules 1956 Govt. of Jharkhand Ranchi (India)
Ref. No. 1323 Date 30 JAN 2025

I, Pasupala Ravi, son of Shri Pasupala Sunkanna, aged 47 years, presently employed as Scientist 'D' at the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (hereinafter referred as MoEF&CC), Regional Office, Ranchi, having office located at 2nd floor, Headquarter- Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand -834002, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am duly authorized by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereby referred as Respondent No. 2) to swear this affidavit and I am conversant with the facts and circumstances of the present case and am thereby competent to depose as under:

BISHWAMBHAR MAHTO NOTARY PUBLIC Reg. No.-17/2018-1804J Ranchi, Jharkhand (India)

2. The present matter has been registered as Suo Moto based on the news item relates to a significant issue of numerous rivers being dried up in the State of Bihar. The article highlights that since the last five-six years, it has become the norm that the rivers are dried up when the summer season arrives. The news item claims that the groundwater level is going down rapidly, which is causing problems to access drinking water.

3. That the answering Respondent no.2 is engaged in, *inter-alia*, policy formulation for abatement, prevention and control of pollution by prescribing environmental standards which are implemented through the Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCBs)/ Pollution Control Committees (PCCs).

4. Besides, the State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees concerned are mandated and empowered to take all such measures as are deemed necessary or expedient for the purpose of protection and improving the quality of environment as well as prevention, control and abatement of environmental pollution.

5. That the Union of India has enacted Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, which specifically deals with issues related to control and abatement of pollution in water bodies including rivers. The implementation of the provisions of the Act is with the Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Boards (SPCBs).

30 JAN 2025

6. That it is submitted that vide S. O. No. 1986 (E) Notification dated 31.07.2014 the subject matter of river Ganga and its tributaries including river Yamuna has been transferred from MoEF&CC to Ministry of Water Resources and

Ganga Rejuvenation (MoWR&GR) now renamed as Ministry of Jal Shakti. A copy of the notification is placed at **Annexure-R1**, wherein it has been decided that conservation, development, management and abatement of pollution of river Ganga and its tributaries shall be dealt by MoWR&GR. The National Mission for Clean Ganga (NMCG) under the Ministry of Jal Shakti is undertaking and supervising the projects/activities for conservation, protection and abatement of pollution in river Ganga and its Tributaries.

7. That it is also submitted that vide Notification No. S.O. 1972(E) dated 14.06.2019 **(Annexure-R2)** the Government of India allocated the business relating to "Conservation, development, management and abatement of pollution of rivers" to Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under Ministry of Jal Shakti.

8. It is humbly prayed that the Hon'ble Tribunal may kindly pass such order(s) as may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of this case.

DEPONENT

डॉ० / Dr. Pasupala Ravi
/ Scientist 'D'
/ Govt. of India
M/o Environment, Forest & Climate Change
Regional Office, Ranchi

30 JAN 2025

NOTARY PUBLIC, RANCHI 30/01/25

30/01/25

Signature Attested and Identification of Lawyer
E/N. 3993/05

VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this day of 2025 that the contents of this reply affidavit based on official record(s) maintained and information available in the office are correct to my knowledge and belief. No part of it is false and nothing has been concealed there from.

DEPONENT

डा० पसुपाला रवि / Dr. Pasupala Ravi
वैज्ञानिक 'डी' / Scientist 'D'
भारत सरकार / Govt. of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
M/o Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची
Regional Office, Ranchi

30/01/25

Signature Attested and Identification of Lawyer
E.No - 3993/05

NOTARY PUBLIC
Regd. No. 17412/03-1804J
Ranchi, Jharkhand (India)

NOTARY PUBLIC, RANCHI
30/01/25

30 JAN 2025

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1556]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2014/श्रावण 10, 1936
No. 1556]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2014/SHRAVANA 10, 1936

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1986(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ छठवां संशोधन नियम, 2014 है।

   (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) "11. पर्यावरण और वन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" ;

(ख) "32. पोत परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"33. कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय।

(i) कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग

(ii) युवक कार्यक्रम विभाग

(iii) खेल विभाग";

(ग) "41. जल संसाधन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"41. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय";

(घ) "42. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन के उप-शीर्षकों का लोप किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) "पर्यावरण तथा वन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय";

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(i) प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"**8**. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण का उपशमन ।

8क. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ।";

(ii) प्रविष्टि 36 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"36क. जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित अन्य सभी मामले ।";

(ग) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. आर्थिक कार्य विभाग " उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 81क और 81ख का लोप किया जाएगा ।;

(घ) "पोत परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,अर्थात्:—

"**5**क. पोत भंजन ।';

(ङ) "पोत परिवहन मंत्रालय" शीर्षक, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

क. कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग

1. उपयुक्त कौशल विकास ढांचा तैयार करने हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय, विद्यमान नौकरियों के लिए ही नहीं अपितु आगे सृजित की जाने वाली नौकरियों के लिए भी व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, नई दक्षता बनाने, नवाचारी सोच और प्रतिभाओं की मार्फत कुशल जनशक्ति में मांग और पूर्ति के बीच अंतर को हटाना ।
2. विद्यमान कौशलों की मैपिंग और उनका प्रमाणीकरण ।

3. शैक्षिक संस्थाओं, व्यापारिक और अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ़ भागीदारी स्थापित करके युवक उद्यमशीलता शिक्षा और क्षमता का विस्तार और इसके लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना।
4. कौशल विकास संबंधी समन्वय की भूमिका।
5. बाजार संबंधी अनुसंधान करना तथा महत्वपूर्ण सेक्टरों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना।
6. उद्योग-संस्थान संपर्क।
7. इस क्रियाकलाप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का घटक लाना – कुशल जनशक्ति की आवश्यकता वाले उद्योग के साथ भागीदारी।
8. बाजार की अपेक्षाओं तथा कौशल विकास के संबंध में अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए व्यापक नीतियां बनाना।
9. सॉफ्ट स्किल्स के लिए नीतियां बनाना।
10. कंप्यूटर शिक्षा।
11. कौशल समुच्चयों के अकादमिक समकक्ष।
12. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों संबंधी कार्य।
13. (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ।
    (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण ।
    (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास ।

ख. युवक कार्यक्रम विभाग

1. युवा कार्य/युवा नीति।
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन।
3. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम।
4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान।
5. ग्रामीण युवा और क्रीड़ा क्लबों को दी जाने वाली सहायता संबंधी स्कीम।
6. राष्ट्रीय युवा आयोग।
7. राष्ट्रीय सेवा स्कीम।
8. स्वयंसेवी युवा संगठन, जिनके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है।
9. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम।
10. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक।
11. युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प, आदि।
12. ब्वाय-स्काउट और गर्ल-गाइड।
13. युवा हॉस्टल।

14. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।

15. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का अवशिष्ट कार्य ।

16. विदेशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान।

ग. खेल विभाग

1. क्रीड़ा नीति ।

2. क्रीड़ा और खेल ।

3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।

4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ।

5. भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण ।

6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिसंघ से संबंधित मामले ।

7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना ।

8. राष्ट्रीय क्रीड़ा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी हैं ।

9. क्रीड़ा छात्रवृत्तियां ।

10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान ।

11. क्रीड़ा अवसंरचना, जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।

12. कोचिंग, टूर्नामेंट, उपस्कर, आदि के लिए वित्तीय सहायता ।

13. संघ राज्य-क्षेत्रों से संबंधित क्रीड़ा मामले ।

14. शारीरिक शिक्षा ।";

(च) "इस्पात मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 में, "पोत भंजन सहित" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(छ) "जल संसाधन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय";

(ज) इस प्रकार प्रतिस्थापित "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(i) प्रविष्टि 1 में, "जल के विविध उपयोगों" शब्दों के पश्चात्, "और नदियों को आपस में जोड़ना" शब्द जोड़े जाएंगे;

(ii) प्रविष्टि 30 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"30क. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जिसके अंतर्गत मिशन निदेशालय, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गंगा संरक्षण से संबंधित अन्य मामले भी हैं ।

30ख. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का संरक्षण,विकास, प्रबंधन और प्रदूषण का उपशमन ।";

(झ) "युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय" शीर्षक, उसके अधीन उप-शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।"।

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/9/2014-मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1986(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Sixth Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in THE FIRST SCHEDULE,—

(a) for the heading "11. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

"11. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Paryavaran, Van aur Jalvaayu Parivartan Mantralaya)";

(b) after the heading "32. Ministry of Shipping (Pot Parivahan Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be inserted, namely :—

"33. Ministry of Skill Development, Entrepreneurship, Youth Affairs and Sports (Kaushal Vikas, Udyamshilta, Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya).

(i) Department of Skill Development and Entrepreneurship (Kaushal Vikas aur Udyamshilta Vibhag)

(ii) Department of Youth Affairs (Yuvak Karyakram Vibhag)

(iii) Department of Sports (Khel Vibhag)";

(c) for the heading "41. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

"41. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Jal Sansadhan, Nadi Vikas aur Ganga Sanrakshan Mantralaya)";

(d) the heading "42. Ministry of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya)" and sub-headings thereunder, shall be omitted.

(2) in THE SECOND SCHEDULE,-

(a) for the heading "MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)" ;

(b) under the heading "MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)" as so substituted,—

(i) for the entry 8, the following entries shall be substituted, namely :—

"8. Conservation, development, management and abatement of pollution of rivers excluding the river Ganga and its tributaries.

8A. National River Conservation Directorate.";

(ii) after the entry 36, the following entry shall be inserted, namely :—

"36A. Climate change and all other matters related thereto.";

(c) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", entries 81A and 81B shall be omitted.;

(d) under the heading "MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALAYA)", after the entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

"5A. Ship breaking.";

(e) after the heading "MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALAYA)", and entries relating thereto, the following heading and sub-headings and entries shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT, ENTREPRENEURSHIP, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (KAUSHAL VIKAS, UDYAMSHILTA, YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (KAUSHAL VIKAS AUR UDYAMSHILTA VIBHAG)

1. Coordination with all concerned for evolving an appropriate skill development framework, removal of disconnect between the demand for and supply of skilled manpower through vocational and technical training, skill up-gradation, building of new skills, innovative thinking and talents not only for the existing jobs but also the jobs that are to be created.

2. Mapping of existing skills and their certification.

3. Expansion of youth entrepreneurship education and capacity through forging strong partnership between educational institutions, business and other community organisations and set national standards for it.

4. Role of coordination relating to skill development.

5. Doing market research and devising training curriculum in important sectors.

6. Industry-Institute linkage.
7. Bringing Public Private Partnership element in this activity-partnership with the industry who need the skilled manpower.
8. Making broad policies for all other Ministries/Departments with regard to market requirements and skill development.
9. To frame policies for soft skills.
10. Computer Education.
11. Academic equivalence of skill sets.
12. Work relating to Industrial Training Institutes.
13. (i) National Skill Development Corporation.
    (ii) National Skill Development Agency.
    (iii) National Skill Development Trust.

B. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS (YUVAK KARYAKRAM VIBHAG)

1. Youth Affairs/Youth Policy.
2. Nehru Yuva Kendra Sangathan.
3. National Reconstruction Corps Scheme.
4. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.
5. Scheme for assistance to Rural Youth and Sports Clubs.
6. National Commission for Youth.
7. National Service Scheme.
8. Voluntary Youth Organisations including financial assistance to them.
9. National Service Volunteer Scheme.
10. Commonwealth Youth Programme and United Nations Volunteers.
11. Youth welfare activities, youth festivals, work camp, etc.
12. Boy-scouts and girl-guides.
13. Youth Hostels.
14. National Youth Awards.
15. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.
16. Exchange of Youth Delegation with foreign countries.

C. DEPARTMENT OF SPORTS (KHEL VIBHAG)

1. Sports Policy.
2. Sports and Games.
3. National Welfare Fund for Sportsmen.
4. Netaji Subhas National Institute of Sports.
5. Sports Authority of India.
6. Matters relating to the Indian Olympic Association and National Sports Federations.
7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and participation of foreign sports teams in international tournaments in India.
8. National Sports Awards including Arjuna Awards.

9. Sports Scholarships.

10. Exchange of Sports persons, experts and teams with foreign countries.

11. Sports infrastructure including financial assistance for creation and development of such infrastructure.

12. Financial assistance for coaching, tournaments, equipment, etc.

13. Sports matters relating to Union territories.

14. Physical Education.";

(f) under the heading "MINISTRY OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)", in entry 1, the words "including ship breaking" shall be omitted;

(g) for the heading "MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely,-

"MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN MANTRALAYA)";

(h) under the heading "MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN MANTRALAYA)", as so substituted,-

(i) in entry 1, after the words "diverse uses of water" the words "and interlinking of rivers", shall be added;

(ii) after the entry 30, the following entries shall be inserted, namely,-

"30A. National Ganga River Basin Authority including the Mission Directorate, National Mission for Clean Ganga and other related matters of Ganga Rejuvenation.

30B. Conservation, development, management and abatement of pollution in river Ganga and its tributaries.";

(i) the heading " MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)" and sub-headings thereunder and entries relating thereto shall be omitted.".

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/9/2014-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1763] नई दिल्ली, सोमवार, जून 17, 2019/ज्येष्ठ 27, 1941

No. 1763] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17, 2019/JYAISTHA 27, 1941

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2019

का.आ. 1972(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ पचासवां संशोधन नियम, 2019 है।

   (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

   (1) प्रथम अनुसूची में,-

   (क) "1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(iii) पशुपालन और डेयरी विभाग" उप-शीर्षक, और "(iv) मत्स्यपालन विभाग" उप-शीर्षक का लोप किया जाएगा;

   (ख) "9कक. पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा;

   (ग) "13. वित्त मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

   "13क. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

   (i) मत्स्यपालन विभाग

   (ii) पशुपालन और डेयरी विभाग";

(घ) "19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"19क. जल शक्ति मंत्रालय

(i) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(ii) पेय जल और स्वच्छता विभाग";

(ङ) "41. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा।

(2). द्वितीय अनुसूची में,-

(i) "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. पशुपालन और डेयरी विभाग" उप-शीर्षक, और "घ. मत्स्यपालन विभाग" उप-शीर्षक, तथा उनके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) "पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय" शीर्षक तथा उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" के अधीन प्रविष्टि 8 तथा प्रविष्टि 8क का लोप किया जाएगा

(iv) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

" मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

क. मत्स्यपालन विभाग

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध मछली-दाना और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में, मत्स्यपालन विभाग के कृत्य, मांगों के प्रतिपादन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।
2. मछली पकड़ना और मछली पालन (अंतरदेशीय, सामुद्रिक तथा राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के परे) और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास।
3. मछुआरों तथा अन्य मछुआरा समूह का कल्याण तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना।
4. मछली पालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।
5. मछली पालन सांख्यिकी।
6. प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछलीधन को हुए नुकसान संबंधी मामले।
7. मछलीधन आयात का विनियमन, करंतीन और प्रमाणीकरण।

8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई।

भाग-II

निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

9. मछलियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।

10. राज्य अभिकरणों/ सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मछली पालन विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

11. मछलीधन का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा मछली रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय।

12. मछलीधन का बीमा।

ख. पशुपालन और डेयरी विभाग

भाग- I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पशुधन और पक्षी-दाना तथा डेयरी और मुर्गीपालन उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।

2. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास।

3. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों का कल्याण।

4. पशुधन और मुर्गीपालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।

5. पशुधन गणना।

6. पशुधन सांख्यिकी।

7. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पशुधन को हुए नुकसान संबंधी मामले।

8. पशुधन आयात का विनियमन, पशु करंतीन और प्रमाणीकरण।

9. गौशाला और गौसदन।

10. कांजीहौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले।

11. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

12. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)।

भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

13. पशु चिकित्सा व्यवसाय वृत्ति।

14. पशुओं और पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।

15. स्वदेशी प्रजातियों में परिवर्तन लाना; पशुधन की स्वदेशी प्रजातियों के लिए केन्द्रीय यूथ पंजी बनाना एवं उनका रखरखाव।

16. राज्य अभिकरणों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेयरी विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

17. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशु और पक्षी रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय।

18. प्रतिपाल्य अधिकरण।

19. पशुधन और पक्षियों का बीमा।

भाग - IV

20. पशु उपयोग और वध से संबंधित मामले।

21. चारा विकास।**"**

(v) "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**"** शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 21 में, **"**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**"** शब्दों के स्थान पर **"**जल शक्ति मंत्रालय**"** शब्द रखे जाएंगे;

(vi) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय**"** शीर्षक तथा उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

"जल शक्ति मंत्रालय"

क. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

I. साधारण

1. राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंध; जल के विविध उपयोगों और नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में जल योजना और समन्वय का संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य।

2. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्।

3. साधारण नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और सिंचाई से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत बहुउद्देशीय, बड़े, मध्यम, लघु और आपातकालिक सिंचाई संकर्म भी आते हैं; नौवहन और जल विद्युत संबंधी जलीय संरचनाएं; नलकूप और भूमि जल का अन्वेषण एवं दोहन; भूमि जल संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षण; धरातलीय और भूमि जल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई, जल प्रबंध, कमान क्षेत्र विकास; जलाशयों और जलाशय अवसादन प्रबंध; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंध, जल-निकास, सूखा नियंत्रण, जल-जमाव और समुद्री कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा।

4. अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास। स्कीमों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन, नदी बोर्ड।

5. जल विधि, विधायन।

6. जल गुणवत्ता निर्धारण।

7. केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का काडर नियंत्रण और प्रबंध।

II. अंतर्राष्ट्रीय पहलू

8. जल संसाधन विकास और प्रबंध, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग और सम्मेलन।

9. अंतर्राष्ट्रीय जल विधि।

10. भारत और पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले; बंगलादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग; सिंधु जल संधि, 1960; स्थायी सिंधु आयोग।

11. जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बाह्य सहायता तथा सहयोग कार्यक्रम।

III. विभाग के अधीन संगठन और निकाय

12. केन्द्रीय जल आयोग।

13. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र।

14. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड।

15. केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण।

16. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र।

17. फरक्का बराज परियोजना।

18. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग।

19. फरक्का बराज परियोजना नियंत्रण बोर्ड।

20. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति।

21. ब्रह्मपुत्र बोर्ड ।

22. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ।

23. बेतवा नदी बोर्ड ।

24. राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान ।

25. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ।

26. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड ।

27. तुंगभद्रा बोर्ड ।

28. अपर यमुना नदी बोर्ड ।

29. जल और विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लिमिटेड (वापकोस) ।

30. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ।

31. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जिसके अंतर्गत मिशन निदेशालय, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गंगा संरक्षण से संबंधित अन्य मामले भी हैं ।

32. नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और नदियों के प्रदूषण का उपशमन ।

33. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

IV. अधिनियमों का प्रशासन

34. उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8) ।

35. अंतर-राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) ।

36. नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 (1956 का 49) ।

37. बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63) ।

38. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) ।

ख. पेय जल और स्वच्छता विभाग

1. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए), मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता; इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक अभिकरणों से संबंधित मामले भी हैं जहां तक उनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल पूर्ति, मल-व्ययन, जल निकास और स्वच्छता से है ।

3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

4. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति परियोजनाओं और मुद्दों से संबंधित विषयों के संबंध में समन्वय।";

(vii) "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक तथा उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/7/2019-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2019.

S.O. 1972(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fiftieth Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

   (1) in THE FIRST SCHEDULE,-

   (a) under the heading "1. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Krishi Evam Kisan Kalyan Mantralaya)", the sub-heading "(iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag)" and sub-heading "(iv) Department of Fisheries (Matsyapalan Vibhag)" shall be omitted;

   (b) the heading "9AA. Ministry of Drinking Water and Sanitation (Peya Jal aur Swachchhata Mantralaya)" shall be omitted;

   (c) after the heading "13. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)" and sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be inserted, namely:-

   "13A. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Matsyapalan, Pashupalan aur Dairy Mantryalaya)

   (i) Department of Fisheries (Matsyapalan Vibhag)

   (ii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag)";

   (d) after the heading "19. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be inserted, namely:-

   "19A. Ministry of Jal Shakti (Jal Shakti Mantralaya)

   (i) Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Jal Sansadhan, Nadi Vikas aur Ganga Sanrakshan Vibhag)

   (ii) Department of Drinking Water and Sanitation (Peya Jal aur Swachchhata Vibhag)";

   (e) the heading "41. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Jal Sansadhan, Nadi Vikas aur Ganga Sanrakshan Mantralaya)" shall be omitted.

   2. in THE SECOND SCHEDULE,-

   (i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN MANTRALAYA)", the sub-heading "C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)" and the sub-heading "D. DEPARTMENT OF FISHERIES (MATSYAPALAN VIBHAG)", and entries thereunder shall be omitted;

   (ii) the heading "MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (PEYA JAL AUR SWACHCHHATA MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted;

(iii) under the heading "MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)", entries 8 and 8A shall be omitted;

(iv) after the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)" and sub-headings and entries thereunder, the following heading, sub-headings and entries shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (MATSYAPALAN, PASHUPALAN AUR DAIRY MANTRYALAYA)

A. DEPARTMENT OF FISHERIES
(MATSYAPALAN VIBHAG)

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest as far as these relate to development of fish feed and fish products with the limitation that in regard to the development of industries, the functions of the Department of Fisheries do not go further than the formulation of the demand and fixation of targets.
2. Promotion and development of fishing and fisheries (inland, marine and beyond territorial waters) and its associated activities, including infrastructure development, marketing, exports, and institutional arrangements etc.
3. Welfare of fishermen and other fisher-folk and strengthening of their livelihoods.
4. Liaison and cooperation with international organizations in matters relating to fisheries development.
5. Fisheries Statistics.
6. Matters relating to loss of fish stock due to natural calamities.
7. Regulation of fish stock importation, quarantine and certification.
8. Fishery Survey of India, Mumbai.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

9. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting fish.
10. Pattern of financial assistance to various State Undertakings, Fisheries Development Schemes through State agencies/Co-operative Unions.

PART III

For the Union territories the subjects mentioned in parts I and II above, so far as they exist in regard to these territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

11. Preservation, protection and improvement of fish stocks and prevention of diseases thereof, veterinary training and practice.
12. Insurance of fish stock.

B. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest as far as these relate to development of livestock and birds feed and dairy and poultry products with the limitation that in regard to the development of industries, the functions of the Department of Animal Husbandry and Dairying do not go further than the formulation of the demand and fixation of targets.
2. Promotion and development of livestock, dairy and poultry and its associated activities, including infrastructure development, marketing, exports and institutional arrangements etc.
3. Welfare of persons engaged in activities relating to livestock, dairy and poultry.

4. Liaison and cooperation with international organizations in matters relating to livestock and poultry development.

5. Livestock Census.

6. Livestock Statistics.

7. Matters relating to loss of livestock due to natural calamities.

8. Regulation of livestock importation, animal quarantine and certification.

9. Gaushalas and Gausadans.

10. Matters relating to pounds and cattle trespass.

11. Prevention of cruelty to animals.

12. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

13. Profession of veterinary practice.

14. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting animals and birds.

15. Conversion of indigenous breeds; introduction and maintenance of Central Herd Books for indigenous breeds of livestock.

16. Pattern of financial assistance to various State Undertakings, Dairy Development Schemes through State agencies/Co-operative Unions.

PART III

For the Union territories the subjects mentioned in parts I and II above, so far as they exist in regard to these territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

17. Preservation, protection and improvement of stocks and prevention of diseases of animals and birds, veterinary training and practice.

18. Courts of Wards.

19. Insurance of livestock and birds.

PART IV

20. Matters relating to cattle utilisation and slaughter.

21. Fodder development."

(v) under the heading "MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (AWASAN AUR SHAHARI KARYA MANTRALAYA)", in the entry 21, for the words "Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation", the words "Ministry of Jal Shakti" shall be substituted;

(vi) after the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading, sub-headings and entries shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF JAL SHAKTI (JAL SHAKTI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN VIBHAG)

I. GENERAL

1. Development, conservation and management of water as a national resource; overall national perspective of water planning and coordination in relation to diverse uses of water and interlinking of rivers.

2. National Water Resources Council.

3. General policy, technical assistance, research and development training and all matters relating to irrigation, including multi-purpose, major, medium, minor and emergency irrigation works; hydraulic structures for navigation and hydro-power; tube wells and groundwater exploration and exploitation; protection and preservation of ground water resources; conjunctive use of surface and ground water, irrigation for agricultural purposes, water management, command area development; management of

reservoirs and reservoir sedimentation; flood (control) management, drainage, drought proofing, water logging and sea erosion problems; dam safety.

4. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys. Implementation of Awards of Tribunals through Schemes, River Boards.

5. Water laws, legislation.

6. Water quality assessment.

7. Cadre control and management of the Central Water Engineering Services (Group A).

II. INTERNATIONAL ASPECTS

8. International organisations, commissions and conferences relating to water resources development and management, drainage and flood control.

9. International Water Law.

10. Matters relating to rivers common to India and neighbouring countries; the Joint Rivers Commission with Bangladesh, the Indus Waters Treaty 1960; the Permanent Indus Commission.

11. Bilateral and external assistance and cooperation programmes in the field of water resources development.

III. ORGANISATIONS AND BODIES UNDER THE DEPARTMENT

12. Central Water Commission.

13. Central Soil and Materials Research Station.

14. Central Groundwater Board.

15. Central Ground Water Authority.

16. Central Water and Power Research Station.

17. Farakka Barrage Project.

18. Ganga Flood Control Commission.

19. Farakka Barrage Project Control Board.

20. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee.

21. Brahmaputra Board.

22. Narmada Control Authority.

23. Betwa River Board.

24. National Institute of Hydrology.

25. National Water Development Agency.

26. Bansagar Control Board.

27. Tungabhadra Board.

28. Upper Yamuna River Board.

29. Water and Power Consultancy Services (India) Ltd. (WAPCOS).

30. National Projects Construction Corporation Limited.

31. National Ganga River Basin Authority including the Mission Directorate, National Mission for Clean Ganga and other related matters of Ganga Rejuvenation.

32. Conservation, development, management and abatement of pollution of rivers.

33. National River Conservation Directorate.

IV. ADMINISTRATION OF ACTS

34. The Northern India Canal and Drainage Act, 1873 (8 of 1873).

35. The Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956).

36. The River Boards Act, 1956 (49 of 1956).

37. The Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976).

38. The Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980).

B. DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION (PEYA JAL AUR SWACHCHHATA VIBHAG)

1. Rural water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned

to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas; International cooperation and technical assistance in this field.

2. Public cooperation, including matters relating to voluntary agencies in so far as they relate to rural water supply, sewage, drainage and sanitation in rural areas.

3. Co-operatives relatable to the items in this list.

4. Coordination with respect to matters relating to drinking water supply projects and issues which cover both urban and rural areas.";

(vii) the heading "MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted.

RAM NATH KOVIND

President

————

[F. No. 1/21/7/2019-Cab.]

RACHNA SHAH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.17 21:41:42 +05'30'